

बेटियों की वरिसत पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

प्रलिमिंस के लयि:

अधकारिों से संबंघति मुद्दे, हद्दि उत्तराधकारि अधनियिम, सर्वोच्च न्यायालय, मतिाकषरा कानून, दयाभाग कानून

मेन्स के लयि:

वरिसत में बेटयिों की हसिसेदारी से संबंघति भारतीय कानून, हद्दि कानून, भारत में महिलाओं से संबंघति मुद्दे।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) (SC) ने फैसला सुनाया है कि वर्ष 1956 के हद्दि उत्तराधकारि अधनियिम (HSA) के तहत कानून के लागू होने से पहले की संपत्तियों पर भी बेटयिों को समान अधकारि होगा।

- इस नरिणय में एक ऐसे व्यक्तकी संपत्तिका विवाद शामिल था, जिसकी वर्ष 1949 में मृत्यु हो गई थी और वह अपने पीछे एक बेटी छोड़ गया था, जिसकी 1967 में मृत्यु हो गई थी।
- इससे पूर्व ट्रायल कोर्ट ने माना था कि चूँकि हद्दि उत्तराधकारि अधनियिम, 1956 के लागू होने से पहले उस महिला की मृत्यु हो गई थी और याचिकाकर्त्ता और उसकी अन्य बहनें उस महिला की मृत्यु की तारीख को वारिस नहीं बनी थीं और इसलिये संपत्ति में हसिसे के विभाजन की हकदार नहीं थीं। बाद में उच्च न्यायालय ने भी नचिली अदालत के खिलाफ अपील खारजि कर दी।

प्रमुख बद्दि

- **वरिसत में बेटयिों की हसिसेदारी:** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक ऐसे व्यक्तकी संपत्ति, जो बनिा वसीयत कयि मर गया और उसकी केवल एक बेटी हो तो उसकी बेटी को संपत्ति में समग्र अधकारि प्राप्त होगा, न कि परिवार के कसिी अन्य सदस्य को।
 - इससे पहले वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में पुरुष उत्तराधकारियों के समान शर्तों पर [हद्दि महिलाओं के लयि पैतृक संपत्ति में उत्तराधकारि](#) और सहदायक (संयुक्त कानूनी उत्तराधकारि) के अधकारि का वसितार कयिा है।
- **प्राचीन ग्रंथ और न्यायकि घोषणाएँ:** सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्राचीन ग्रंथों (स्मृति), प्रसदिध वदिवानों की टपिपणयिों और यहाँ तक कि न्यायकि घोषणाओं का उल्लेख कयिा है, जनिहोंने कई महिला उत्तराधकारि के रूप में, पत्नयिों और बेटी के अधकारिों को मान्यता दी है।
 - वरिसत पर प्रथागत हद्दि कानून के स्रोतों का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 'मतिाकषरा कानून' पर चर्चा की।
 - SC ने शायमा चरण सरकार वदिया भूषण द्वारा हद्दि कानून के एक डाइजेसट, 'व्यवस्था चंदरकि' को भी देखा जिसमें 'वृहस्पति' को यह कहते हुए उद्धृत कयिा गया था कि पत्नी को उसके पति की संपत्तिका उत्तराधकारि घोषति कयिा जाता है तथा उसकी अनुपस्थति में एक पुत्र के रूप में बेटी उसके वंश को आगे बढ़ाती है।
 - SC ने यह भी नोट कयिा कि पुस्तक में मनु द्वारा कहा गया है कि "एक आदमी का बेटा उसका उत्तराधकारि होता है और बेटी बेटे के बराबर होती है। फरि कोई अन्य उसकी संपत्तिका वारिस कैसे बन सकता है, उसके जीवति रहने के बावजूद, जो कि जैसा है, वैसा ही है"।
- **पुराना कानून: एक वधिवा या बेटी का स्व-अरजति संपत्तिका उत्तराधकारि या एक हद्दि पुरुष की सहदायकि संपत्तिके विभाजन में प्राप्त हसिसे का अधकारि पुराने प्रथागत हद्दि कानून के तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।**
 - यदि एक मृत हद्दि पुरुष की नरिवसीयत संपत्ति एक स्व-अरजति संपत्ति है या एक सहदायकि या पारिवारिक संपत्तिके विभाजन में प्राप्त संपत्ति है तो वह उत्तरजीवति द्वारा हस्तांतरति होगी न कि उत्तरजीवति द्वारा, और ऐसे हद्दि पुरुष की बेटी हकदार होगी कि इस तरह की संपत्ति में उसे अन्य की अपेक्षा वरीयता प्राप्त हो।
- **महिला की मृत्यु के बाद संपत्ति:** न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर एक हद्दि महिला बनिा कसिी उत्तराधकारि के मर जाती है, तो उसके पति या माता से वरिसत में मलिी संपत्ति उसके पति के उत्तराधकारियों के पास जाएगी, जबकि उसके पति से प्राप्त संपत्ति ससुर के वारसिों के पास जाएगी।

भारत में भूमिअधकारि और महिलाएँ

- **संबंधति डेटा:** भारत में संपत्ति बड़े पैमाने पर पुरुष उत्तराधकारियों को हस्तांतरति करने के इच्छुक हैं। यह बदले में महिलाओं को वत्तितीय स्वतंत्रता

और उद्यमिता से वंचित करता है।

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार**, 43% महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पास अकेले या संयुक्त रूप से घर/भूमि है, लेकिन वास्तव में संपत्ता तिक पहुँच और महिलाओं की नयितरण क्षमता के बारे में संदेह बना हुआ है।
 - वास्तव में, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के 2020 के एक वरकगि पेपर में ग्रामीण जमींदार घरों में बमुश्किल 16% महिलाओं के पास अपनी जमीन है।
- **पतिसत्ता:** गहरे पतिसत्तात्मक रीति-रिवाजों और ग्रामीण-कृषि व्यवस्था में संपत्ति, जिसे धन के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा जाता है, का अधिकार काफी हद तक पुरुष उत्तराधिकारियों को दिया जाता है।
- **राज्य कानून:** कृषि भूमि के लिये वरिसत कानूनों में केंद्रीय व्यक्तिगत कानूनों और राज्य कानूनों में परस्पर वरिोध है।
 - इस संबंध में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (यूपी) और यहाँ तक कि दिल्ली जैसे राज्यों में परतगामी उत्तराधिकार प्रावधान हैं।
 - वास्तव में हरियाणा ने दो बार HSA, 1956 के माध्यम से महिलाओं को दिये गए परगतशील अधिकारों को छीनने की कोशिश की, जबकि यूपी में वर्ष 2016 से विवाहित बेटियों को प्राथमिक उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है।
- **जमीनी स्तर पर वरिोध:** कई उत्तर भारतीय राज्यों में महिलाओं के लिये जमीन के पंजीकरण का जमीनी स्तर पर वरिोध भी हो रहा है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण और संपत्ति का अधिकार एक अधूरी परियोजना बनी हुई है।

हद्वि उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:

परचिय:

- हद्वि कानून की मतिाक्षरा धारा को हद्वि उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया, संपत्ति के वरिस एवं उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत परबंधित किया गया, जिसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी।
- यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सखि, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के तहत हद्वि माना गया है।
- एक अवभाजित हद्वि परिवार में कई पीढ़ियों के संयुक्त रूप से कई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति की संयुक्त रूप से देख-रेख करते हैं।
- **हद्वि उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम [Hindu Succession (Amendment) Act], 2005:**
 - 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक/कॉपरसनर के रूप में मान्यता दी गई।
 - अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए एक कॉपरसनर की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान कॉपरसनर माना गया।
 - इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियाँ दी गईं।
 - यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नयिम को लागू करता है, जहाँ उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि एक इच्छा-पत्र के माध्यम से।

हद्वि कानून से संबंधित वधियाँ/नयिम

मतिाक्षरा कानून	दयाभागा कानून
मतिाक्षरा पद की उत्पत्ति याज्ञवल्क्य स्मृति पर वजिजानेश्वर द्वारा लिखित एक टीका के नाम से हुई है।	दयाभाग पद जमितवाहन द्वारा लिखी गई, समान नाम की पुस्तक से लिया गया है।
भारत के सभी भागों में इसका परभाव देखने को मलिता है और यह बनारस, मथिला, महाराष्ट्र एवं द्रवडि शैली में उप-वभाजित है।	बंगाल और असम में इसका परभाव देखने को मलिता है।
जन्म से ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में पुत्र की हसिसेदारी होती है।	पुत्र का संपत्ति पर जन्म से कोई स्वामित्व/अधिकार नहीं होता है, परंतु वह अपने पति की मृत्यु के बाद स्वतः ही इस अधिकार को प्राप्त कर लेता है।
एक पति के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान परिवार के सभी सदस्य को कॉपरसनर का अधिकार प्राप्त होता है।	पति के जीवनकाल में पुत्र को कॉपरसनर का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
इसमें कॉपरसनर का भाग परभाषित नहीं है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।	प्रत्येक कॉपरसनर के हसिसे को परभाषित किया गया है और इसे समाप्त किया जा सकता है।
पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकिन उसे अपने पति और पुत्रों के बीच किसी भी बँटवारे में हसिसेदारी का अधिकार प्राप्त है।	यहाँ महिलाओं के लिये समान अधिकार मौजूद नहीं है क्योंकि पुत्र बँटवारे की मांग नहीं कर सकता है और यहाँ पति ही पूर्ण मालिक होता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस